



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

भ० 2]
No. 2]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न की जाती हैं जिससे यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—हाउ 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सार्विधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 1980

क्र०निःधा० 4—राजपत्र, मविधान के अनुच्छेद 309 के प्रभावक
द्वारा प्रदर्श शक्तियों का प्रयोग करने द्वा, नौमेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिण्वन्द) पद भर्ती नियम, 1979 का संशोधन करने के लिए निम्न-
लिखित नियम बनाये हैं, श्रवति —

1. (1) सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — इन नियमों का सक्षिप्त नाम
नौमेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिण्वन्द) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रश्नत होगे।

2. नौमेना समूह 'ग' (शैक्षणिक कर्मचारिण्वन्द) पद भर्ती नियम, 1979
के नियम 6 में, "या पदों" प्रबद्धों का लोप किया जाएगा।

[फाइल सं. ०००००० (एस०सी०)/2842]
उमाकाल मिश्र, अध्यक्ष सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 26th December, 1980

S.R.O. 4.—In exercise of the powers conferred by the
proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby
makes the following rules to amend the Navy Group 'C' (In-
structional Staff) Posts Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) Short title and commencement—These rules may be
called the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruit-
ment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publi-
cation in the Official Gazette.

2. In the Navy Group 'C' (Instructional Staff) Posts Recruit-
ment Rules, 1979, in rule 6, the words "or posts" shall
be omitted.

[File No. CP(SC)/2842]

UMA KANT MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

क्र०निःधा० 5—केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 1924
(1924 का 2) की धारा 280 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने
द्वा, छावनी नियम, 1937 में कठिनप्य और संशोधन करना
चाहती है। ऐसा कि उक्त धारा 280 में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों
का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी शक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित
किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है
और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मात्र दिन की अवधि के अवधान पर
या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपर विनिर्दिष्ट साल दिन की अवधि के शीतार उक्त प्रारूप की
बाबत जो भी आवश्यक या सुसाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होगे, केन्द्रीय सरकार
उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम छावनी नियम संवेदन (संशोधन)
नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में अलिम रूप से प्रकाशित होने की तारीख को
प्रदृश होगे।

2 छावनी निधि सेवक नियम, 1937 (जिसे इसमें उसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 में,

(i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(कक्ष) छावनी निधि सेवक के सम्बंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, यथास्थिति, (i) वह प्राधिकारी जो उस पद पर जिस पर सेवक तत्त्वमय है नियुक्त करने के लिए सक्षम है, या (ii) वह प्राधिकारी जिसने सेवक को उस पद पर नियुक्त किया है, इनमें से जो भी प्राधिकारी उच्चतर प्राधिकारी है;

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(गग) ‘भनुशासनिक प्राधिकारी’ से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो इन नियमों के प्रधीन किसी सेवक पर नियम 11 में चिनिर्विषट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिरोपित करने के लिए सक्षम है”;

(iii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घघ) ‘पर्यवेक्षी पद’ से किसी ओर्डर के प्रधीन ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो “पर्यवेक्षी पद” नहीं है”;

(iv) खण्ड (च) में “किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा सेवक नहीं है जो ऐसे पद पर सेवा कर रहा है जिसके लिए लोक राजस्व से पेशन दी जाती है” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(v) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(चच) “पर्यवेक्षी पद” से किसी ओर्डर के प्रधीन कोई ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जिसे केन्द्रीय सरकार ने या उस के द्वारा इस नियमित प्राधिकृत प्राधिकारी ने पर्यवेक्षी पद घोषित कर दिया है;

(vi) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ज) छावनी निधि सेवक के संबंध में “अस्थायी सेवक” के अन्तर्गत नियम 9 के प्रधीन मंजूर किए गए किसी अस्थायी पद के पदधारी के अतिरिक्त ओर्डर के प्रधीन अधिक्षिण्यायी या स्थायी पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त पदधारी है;

3. उक्त नियमों के नियम 3 में “तत्पश्चात् भारत वासन प्रधिनियम, 1935 के प्रधीन उपनियम” शब्दों और दोनों का लोप किया जाएगा;

4. उक्त नियमों के नियम 5 के प्रथम परन्तुक में “पचास रुपए प्रति मास से अन्यून” शब्दों के स्थान पर “दो श्री पचास रुपए प्रति मास से अन्यून” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 5 खं में (क) उपनियम (3) के विभाग परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक से ओर्डर के सेवकों की परिचय के लिए ओर्डर द्वारा नियुक्त चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है”;

(ख) उप नियम (8) में “प्रत्येक ओर्डर द्वारा” शब्दों के स्थान

पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् —

“(1) पर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां ओर्डर द्वारा और पर्यवेक्षी पदों पर सभी नियुक्तियां कार्यपालक प्रधिकारी द्वारा की जाएंगी”।]

7. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में आरम्भ में निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् — “ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुये जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर इस नियम जारी करे”,

8. उक्त नियमों के नियम 8 में,—

(1) उपनियम (4) में आधिकारिक शब्द “ओर्डर” के स्थान पर “कार्यपालक प्राधिकारी” शब्द रखे जायेंगे;

(2) उपनियम (5) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और भी किसी अस्थायी सेवक की सेवा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सूचना दे कर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी किन्तु उसके होते हुये भी किसी ऐसे सेवक की सेवा तुरन्त समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार सेवा-समाप्ति पर सेवक यथास्थिति, सूचना की अवधि उम्म प्रधिति के लिये जो सूचना से एक मास कम है उसी दर पर बेतन और भत्ते की रकम के समतुल्य रकम का बांदा करने का हक्कार होगा जिस पर वह सेवा समाप्ति से ठीक पूर्ण बेतन और भत्ते ले रहा था।”

9. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“9. जब ओर्डर के समाप्ति की रात में अस्थायी सेवकों का नियोजन आवश्यक है तब वह ऐसी घटी पर जो आवश्यक समझी जाये छह मास की कुल अवधि के लिये ऐसे पदों का सूचन करने की मंजूरी दे सकता है और ऐसे पदों पर नियुक्ति सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी :

परन्तु—

(क) इस शर्ति का प्रयोग करने समय ओर्डर का समाप्ति किसी कार्ये विशेष के लिये अस्थायी पदों के सूचन को प्रतिषिद्ध करने वाले ओर्डर के आदेश का उल्लंघन भी करेगा और ओर्डर के आगामी प्रधिवेशन में अनुमोदन के लिये कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा की गई, प्रत्येक नियुक्ति की लिखित रूप में रिपोर्ट देगा।

(ख) ओर्डर का समाप्ति पुष्टि के लिये ऐसी सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट कमान के मुख्य सभावेशक प्राधिकारी को देगा रिपोर्ट ओर्डर के अनुमोदन के पश्चात् खण्ड (क) के अनुभार की जायेगी जिसके साथ उन घटों का पूर्ण स्पष्टीकरण भी संलग्न होगा जिनके कारण नियुक्तियां करती हैं ; और

(ग) ऐसी किसी नियुक्ति की वावत ओर्डर का अनुमोदन या कमान के मुख्य भागादेशक प्राधिकारी द्वारा पुष्टिकरण को रोक लिये जाने पर नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।”

10. उक्त नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“10. क. (1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी सेवक को निम्नलिखित वशाओं में विलम्बित कर सकता है,—

(क) जब उसके विहृ अनुशासनिक कार्यवाही अनुभात है या लम्बित है; या

- (ब) जब उसके विषद् किसी दायिक अपराध की बाबत कोई भासला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है।
- (2) किसी सेवक की नियुक्ति प्राधिकारी के आवेदा से :—
- (क) यदि वह अपराधिक अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के लिये प्रभिकारी में निष्ठ है, तो अपने निष्ठ किये जाने की तारीख से,
- (ख) किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने की दशा में अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के कारावास से दण्डित किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है प्रथमा प्रनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया गया है, अपनी दोषसिद्धि की तारीख से निलंबनाधीन समझा जायेगा।
- स्पष्टीकरण—**—इस उपनियम के खण्ड (ब) में निरिष्ट अड़तालीस घंटे की प्रवधि की संरणाना, दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास की कोई अंतरिक्ष अवधि है, तो इस प्रयोजन के लिये बनना में सी जाएगी।
- (3) यदि निलंबनाधीन किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या प्रनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन पर अपास्त कर दी जाती है और वह भासला अंतरिक्ष जांच या कार्रवाई करने के लिये या किन्हीं अन्य नियमों के साथ प्रेरित कर दिया जाता है, तो उसके निलंबन का अवेदा पदच्युति, हटाये जाने या प्रनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उससे प्रवृत्त बुझा भासला जायेगा, और आगे आवेदा होने तक प्रवृत्त रहेगा।
- (4) यदि किसी सेवक पर अधिरोपित की गई सेवा से पदच्युति, हटाये जाने या प्रनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति किसी विधि व्यावालय के किसी विनियोग के परिणामस्वरूप या उसके हारा अपास्त कर दी जाती है या शूल बोधित कर दी जाती है या शूल कर दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी भासले की परिस्थिति पर विचार करके वह विनियोग करता है कि उसके विषद् उन अधिकार्यों पर, जिन पर पदच्युति, हटाये जाने या प्रनिवार्य सेवा निवृत्ति की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अंतरिक्ष जांच की जाये तो उस सेवक के बारे में यह समझा जायेगा कि वह उस पदच्युति, हटाये जाने या प्रनिवार्य सेवा निवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हारा निन्दित कर दिया गया है और आगे आवेदा होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा।
- (5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक वह ऐसे प्रधिकारी हारा उपालंसित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है जो ऐसा करने के लिये सक्षम है।
- (ख) यदि कोई सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यालय के संबंध में या अन्यथा) निलंबित किया गया समझा जाता है और उस निलंबन के बालू रहने के दौरान उसके विषद् कोई अन्य अनुशासनिक कार्यालयी प्रारम्भ की जाती है तो वह प्रधिकारी जो उस निलंबित करने के लिये सक्षम है, उन कारणों से जो उसके हारा लेखदृढ़ किये जायेंगे, वह निदेश दे सकेगा कि कार्यालयी ऐसी सभी या किन्हीं कार्यालयों के समाप्त होने तक निलंबनाधीन बना रहेगा।
- (ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा

वह तक उसे उपालंसित या प्रतिसंहृत करने के लिये समझ प्राधिकारी हारा या ऐसे किसी प्राधिकारी हारा, जिसका वह प्राधिकारी अद्वीनस्थ है, उपालंसित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता।

11. उस नियम के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"11 (1) कार्यपालक प्राधिकारी किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से जो लेखदृढ़ किये जायेंगे निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियाँ—

- (1) परिनिवृत्त;
- (2) जुमना;

(2) नियुक्त प्राधिकारी, किसी सेवक पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से और उसमें इसके पश्चात् जैसा उपर्याप्ति है उसके अनुसार निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित कर सकता है, अर्थात् :—

छोटी शास्तियाँ—

- (1) उसकी प्रोत्साहनी रोकना;
- (2) उसकी उपेक्षा या आवेदा-बंग के कारण बोर्ड को हुई कोई धन सम्बन्धी सम्पूर्ण हानि या उसका कोई भाग, उसके बेतन से बसूल करना;
- (3) बेतन बूझी रोकना;

बड़ी शास्तियाँ—

(4) काल-बेतन मान के किसी निम्नतर प्रक्रम पर विनियोग अवधि के लिये ऐसे अवतिरिक्ष नियमों सहित अवनति कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सेवक बेतन बूढ़िया उपालंसित करेगा या नहीं और ऐसे करने या न करने के प्रभाव से उसकी भावी बेतन बूढ़िया मूलधी होगी या नहीं ;

(5) किसी निम्नतर काल-बेतनमान, श्रेणी, पद या भेदा में ऐसी अवनति जो भासली और पर सेवक के उस काल बेतनमान, बतन, श्रेणी, पद या सेवा में पिससे उसकी अवनति की गई है, प्रोत्साहनी, के लिये बर्जन होने और जो उस श्रेणी या पद या सेवा में जिससे सेवक की अवनति की गई है, पुनः स्थापन की जाती की बाबत और उस श्रेणी या पद या सेवा में ऐसे पुनः स्थापन पर उसकी उपेक्षा और बेतन की बाबत अवतिरिक्ष नियमों सहित या रहित होगी ;

(6) प्रनिवार्य सेवा निवृत्ति ;

(7) सेवा से हटाया जाना जो बोर्ड के अधीन जिसकी सेवा में वह या किसी अन्य बोर्ड से भावी नियोजन के लिये निरहंरका न होगी ;

(8) सेवा से पदच्युति जो उस बोर्ड के अधीन जिसके अधीन वह पदच्युति के समय नियोजित या या किसी अन्य बोर्ड के अधीन भावी नियोजन के लिये मासूली तौर पर निरहंरका होगी ।

स्पष्टीकरण.—इस नियम के प्रथमांशें निम्नलिखित की शास्ति नहीं माना जायेगा, अर्थात् :—

- (1) सेवक को काल बेतन मान में दक्षता रोध पर इस आधार पर रोकना कि वह दक्षता रोध पर करने के लिये अधोग्रह है,

- (2) सेवक के मामले पर विचार करने के पश्चात् उसकी उस श्रेणी या पद पर जिस प्रोत्साहन के लिये जह पात्र है, प्रधिकारीया या स्थानापन्न हैंसियत में प्रोत्साहन न करना;
- (3) ऐसे सेवक का, जो उच्चवार सेवा, श्रेणी या पद पर स्थापन्न है से कार्य कर रहा है, जिम्मेदार श्रेणी या पद पर इस आवार के लिये कि उसे ऐसी उच्च सेवा श्रेणी या पद के लिये उपयुक्त नहीं समझा जाता है या ऐसे प्रशासनिक आधार (प्राधारो) पर, जो उसके आवारण से सम्बद्ध नहीं है, प्रतिवर्तन;
- (4) ऐसे सेवक का जो किसी अस्थि सेवा, श्रेणी या पद पर परिवर्तीका पर नियुक्त किया गया है, परिवर्तीका की प्रवधि के दौरान या उसके अन्त में उसकी स्थायी सेवा श्रेणी या पद पर, उसकी नियुक्ति के निष्पत्तिनों या ऐसी परिवर्तीका को शासित करने वाले नियमों और भावेषों के अनुसार, प्रतिवर्तन;
- (5) कर्मचारी की उन उपबन्धों के अनुसार अनिवार्य सेवा से निवृति जो उसकी अधिवर्धिता या सेवा निवृति के संबंध में है;
- (6) (क) परिवर्तीका पर नियुक्त किसी सेवक की उसकी परिवर्तीका की प्रवधि के दौरान या अन्त में उसकी नियुक्ति के निष्पत्तिनों के या ऐसी परिवर्तीका को शासित करने वाले नियमों और भावेषों के अनुसार, या
 (ख) किसी अस्थायी कर्मचारी की नियम 8 के उपनियम (5) के अधीन सेवा की समाप्ति, या
 (ग) किसी कारार के निष्पत्तिनों के अधीन नियोजित किसी सेवक की उस कारार के निष्पत्तिनों के अनुसार।

परन्तु--

- (i) जिन श्रेणी सेवक से सिन्ह किसी श्रेणी के सेवक पर जुर्माना नहीं किया जाएगा और किसी भी मास में जुर्माने की कुल रकम उस सीमा से अधिक नहीं होगी जो केवल य सरकार द्वारा समय समय पर विनियिष्ट की जाये;
 (ii) इस नियम के अधीन आवंपालक अधिकारी द्वारा हिए एवं इष्टों की एक सूची प्रति मास बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।"

12. उक्त नियमों के नियम 11के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्--

"11क. किसी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आरम्भ की जा सकती है।"

13. उक्त नियमों के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएं, अर्थात्--

"12(1) नियम 11 के बाप्त (iv) से (viii) में विनियिष्ट शास्त्रिया अधिरोपित करने वाला कोई भी भावेण, जहाँ तक संभव हो, इस नियम और नियम 11 में उपबन्धित रोति से जांच कर लेने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) जब किसी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि किसी सेवक के विवर आवार या कादावार के किसी लाठन की सच्चाई की जांच करने के लिए आधार है, तब उसकी सच्चाई की जांच यथास्थिति वह स्वयं कर सकेगा या ऐसा करने के लिए इस नियम के अधीन प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:- जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है वहाँ नियमों में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी भी निर्वेश का अर्थ वह लगाया जाएगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।

(3) जही किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस नियम या नियम 12के प्रधीन जांच करने की प्रस्थापना है, वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी--

- (i) आवार या कादावार के लाठनों के सार को आरोपों के निवित्त और सुमित्र अनुच्छेदों में;
 (ii) आरोपों के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में आवार या कादावार के लाठनों का विवरण, जिसमें--
 (क) सभी सुसंगत तथ्यों का कथन जिसके प्रतिवर्त कर्मचारी द्वारा की गई कोई स्वीकृति या संस्वीकृति नहीं है,
 (ख) उन दस्तावेजों की सूची, जिनके द्वारा और उन साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों का समर्थक किए जाने की प्रस्थापना है; अनुचिष्ट होंगे;

सेवक द्वारा कराएगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की आवार या कादावार के लाठनों के विवरण की एक-एक प्रति और उन दस्तावेजों और साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद को समर्थित करने की प्राप्तापना है, सेवक को परिवर्त करेगा या कराएगा और सेवक से वह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर जो विनियिष्ट किया जाए, अपनी प्रतिरक्षा का एक लिखित कथन प्रस्तुत करे और वह अताएँ कि क्या वह आहता है कि उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाए।

(5) (क) प्रतिरक्षा के विनियिष्ट कथन की प्रति पर अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों को, जो स्वीकार नहीं किए गए हैं जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसे करना आवश्यक समझते तो उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा और जहाँ सेवक ने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप के सभी अनुच्छेद स्वीकार कर लिए हैं वह अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा साक्ष लेने के पश्चात् जैसा वह लोक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने नियक्ष अभिलिखित करेगा और नियम 12के प्रधिकारित सेवक कोई करेगा।

(ख) यदि प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन सेवक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं कर सकेगा या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए एक जांच प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोप के किसी अनुच्छेद की जांच स्वयं करता है या ऐसा आरोप की जांच करने के लिए किसी जांच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, वहाँ वह आरोप के अनुच्छेदों के समर्थन में अपनी और से मामले को उपस्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगा, जैसे उपस्थापक प्राधिकारी कहा जाएगा।

(8) अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ वह जांच प्राधिकारी नहीं है, जांच प्राधिकारी की निम्नलिखित भेजेगा--

- (i) आरोप के अनुच्छेदों और आवार या कादावार के लाठनों के विवरण की एक प्रति;
 (ii) यदि सेवक ने प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन किया है तो उसकी एक प्रति;
 (iii) उपनियम (3) में विनियिष्ट साक्षियों के, यदि कोई हैं, कथनों की एक प्रति;
 (iv) सेवक की उपनियम (3) में विनियिष्ट दस्तावेजों का परिवान साक्षित करने वाला साक्षय और.

- (v) "उपस्थापक प्राधिकारी" को नियुक्ति के प्रावेश की एक प्रति।
- (7) सेवक, उसके द्वारा आरोप के अनुच्छेदों, अवकाश या कदाचार के लाभों के विवरण की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के भीतर उस दिन और उस समय पर जो जांच प्राधिकारी नियुक्त सूचना द्वारा इस निमित्त विनियिष्ट करे या उस दिन से अनधिक ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो जांच प्राधिकारी अनुज्ञास करे, जांच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थिति होगा।
- (8) (क) सेवक अपनी ओर से मामला पेश करने के लिए किसी ग्रन्थ सेवक की सहायता ले सकता, किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई विधि व्यवसायी तब तक कियुक्त नहीं करेगा जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापक प्राधिकारी विधि व्यवसायी नहीं है या अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी अनुज्ञा नहीं देता है।
- टिप्पणी—सेवक किसी ऐसे सेवक की सहायता नहीं ले गा जिसके पास दो ऐसे अनुशासनिक मामले लंबित हैं, जिनमें उसे सहायता देनी है।
- (म) सेवक अपनी ओर से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आरोप द्वारा इस निमित्त विनियिष्ट करे किसी सेवा निवृत्त सेवक की सहायता ले सकता है।
- (9) यदि सेवक जिसमें आरोप के अनुच्छेदों में से किसी की प्रतिरक्षा के अवधारणा नहीं किया है या प्रतिरक्षा को कोई विवित कथन में स्वीकार नहीं किया है, जांच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति होती है, तो ऐसे प्राधिकारी उसमें पूछेगा कि क्या वह दोषी है या उसे कोई प्रतिरक्षा करनी है और यदि वह आरोप के अनुच्छेद में से किसी के दोषी होने का प्रभिकथन करता है तो जांच प्राधिकारी उस अधिवचन को प्रभिलिखित करेगा, अधिले ख पर हस्ताक्षर करेगा और सेवक से उस पर हस्ताक्षर कराएगा।
- (10) जांच प्राधिकारी आरोप के उन अनुच्छेदों के बारे में, जिनका दोषी होने का अधिवचन सेवक करता है, दोषी होने का निष्कर्ष लेगा।
- (11) यदि सेवक विनियिष्ट समय के भीतर उपस्थिति होने में असफल रहता है या अधिवचन करने से इनकार करता है या ऐसा करने में लंघ करता है, तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह उस साक्ष्य को पेश करे जिससे वह आरोप के अनुच्छेदों की साक्षित करने की प्रस्थापना करता है और मामले को, यह प्रावेश अधिलिखित करने के पश्चात् तीस दिन से अनधिक की पश्चात्वती सारीख के लिए स्थगित कर देगा कि सेवक अपनी प्रतिरक्षा सेयार करने के प्रयोजन के लिए—
- आवेदन से पांच दिन के भीतर या पांच दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर, जिनमें जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उपनियम (3) में विनियिष्ट सूची में विनियिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;
 - उम साक्षियों की, जिनकी परीक्षा उसकी ओर से की जाती है, ऐक सूची प्रस्तुत कर सकता है,
 - आवेदन से दस दिन के भीतर या दस दिन से अनधिक इतने अतिरिक्त समय के भीतर, जिनमें जांच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, ऐसी दस्तावेजों के जो बोर्ड के कब्जे में हैं किन्तु जो उपनियम (3) में विनियिष्ट सूची में उल्लिखित
- नहीं है प्रकटीकरण या प्रस्तुत करने की सूचना दे सकता है।
- (12) जांच प्राधिकारी, दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, वह सूचना या उसकी प्रतिया, दस्तावेजों को उस तारीख तक पेश करने की प्रध्यायेक्षा के साथ, जो ऐसी अध्यायेक्षा में विनियिष्ट की जाए, उस प्राधिकारी को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं, प्रमोरित करेगा।
- परन्तु जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों की, जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं है, उन कारणों से जिन्हें वह लेखांचल करेगा, अध्यायेक्षा करने से इकार कर सकता है।
- (13) उपनियम (12) में विनियिष्ट अध्यायेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक प्राधिकारी, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अध्यायेक्षा दस्तावेजों हैं, उन्हें जांच प्राधिकारी के सामने पेश करेगा—
- परन्तु यदि उस प्राधिकारी का, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में, अध्यायेक्षा दस्तावेज है, उन कारणों से, जिन्हें वह लेखांचल करेगा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किन्तु दस्तावेजों का पेश किया जाना लोकहित के विचार होगा, तो वह जांच प्राधिकारी को तदनुसार सूचित करेगा और ऐसी सूचना मिलने पर जांच प्राधिकारी वह सूचना सेवक को संसूचित करेगा और उस अध्यायेक्षा को जो उसने ऐसी दस्तावेजों को पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की है, वापस ले लेगा।
- (14) जांच के लिए नियत तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसा मौखिक या दस्तावेजी माध्यम पेश किया जाएगा, जिसके द्वारा आरोपों के अनुच्छेदों के सावधान किए जाने की प्रस्थापना है। मालिकों की परीक्षा ऐसे सेवक द्वारा या उसकी ओर से की जा सकती है उपस्थापन प्राधिकारी को जो साक्षियों की ऐसी किन्तु बातों पर पुक़ार परीक्षा करने का हक होता है जिन पर उन की प्रति परीक्षा की गई है। किन्तु जांच प्राधिकारी को इजाजत के बिना किसी नई बात पर पुक़ार परीक्षा करने का हक नहीं होता है। जांच प्राधिकारी भी मालिकों से ऐसे प्रश्न पूछ सकता जो वह ठीक समझता है।
- (15) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले के बदल किए जाने से पूर्व आवश्यक प्रतीत होता है तो जांच प्राधिकारी उपस्थापन प्राधिकारी को ऐसा मालिक प्रस्तुत करने की अनुज्ञा स्वाक्षिकानुसार देसकेगा जो सेवक की वी गई सूची में सम्मिलित नहीं है या स्वयं नया साक्ष्य मांग मकेगा या किसी मालिक को पुनः बुला सकेगा या उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में सेवक ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की जिसे पेश किए जाने की प्रस्थापना है, एक प्रति यदि वह उसकी मालिक करता है, प्राप्त करने का और ऐसे नए साक्ष्य के पेश किए जाने से पूर्व पूरे तीन दिन के लिए जांच स्थानित की गई है, अपवर्जित किए जाएं, लूकांचल होता है। जांच प्राधिकारी, ऐसी दस्तावेजों को अधिले ख पर लाने के पूर्व सेवक को उनके निरीक्षण करने का आवश्यक प्रवान देसकेगा। यदि जांच प्राधिकारी की राय है कि किसी साक्ष्य का पेश किया जाना न्याय के हिन में आवश्यक है तो वह सेवक को भी ऐसा नया साक्ष्य पेश करने की अनुज्ञा देसकेगा।
- (16) जब अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बदल कर विधा जाता है तब सेवक से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा का कथन मौखिक या लिखित रूप में, जैसा वह चाहे करे यदि मौखिक प्रतिरक्षा की जाए है तो उसे अभिलिखित किया जाएगा और सेवक से अधिले ख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी। दोनों में से किसी भी दिशा में

- प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति उपस्थापन अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया है, दी जाएगी।
- (17) तब सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जाएगा। सेवक, यदि वह लाहू है तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षा कर सकता है। तब उन मालियों की परीक्षा की जाएगी जो सेवक द्वारा पेश किए जाएँ और अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से उनकी प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा और परीक्षा सालियों को लागू उपबन्धों के अनुमार की जा सकती है।
- (18) जांच प्राधिकारी, सेवक द्वारा अपना मामला बन्द कर दिए जाने के पश्चात् इस प्रयोजन के लिए कि सेवक अपने विश्व साक्ष्य में प्रकट होने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देने में समर्थ हो सके, साक्ष्य में सेवक के विश्व प्रकट होने वाली किन्तु परिस्थितियों के बारे में उससे साधारणतः प्रश्न कर सकेगा और यदि सेवक ने स्वयं परीक्षा नहीं की है तो ऐसा अवश्य करेगा।
- (19) जांच प्राधिकारी, साक्ष्य का पेश किया जाना पूरा हो जाने के पश्चात् उपस्थापन अधिकारी की, यदि कोई नियुक्त किया गया है और सेवक की सुनवाई कर सकेगा या यदि वे ऐसा चाहे तो, उन्हें अपने-अपने मामले के लिखित संक्षेप फाइल करने की अनुशा दे सकेगा।
- (20) यदि वह सेवक जिसे आरोप के अनुच्छेदों की एक प्रति दी गई है, उस प्रयोजन के लिए विनिरिप्ट तारीख को या उससे पूर्व प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश नहीं करता है या जांच प्राधिकारी के मामले स्वयं उपस्थित नहीं होता है या इस नियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में अन्यथा असफल रहता है या अनुपालन करने से छनकार करता है, तो जांच अधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकेगा।
- (21)(क) जहां उस अनुशासनिक प्राधिकारी ने जो नियम 11 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिरिप्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिगोपित करने के लिए सक्षम है। किन्तु नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) से (viii) में विनिरिप्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिगोपित करने के लिए सक्षम नहीं है किसी आगेप के अनुच्छेदों की जांच स्वयं की है या कराई है और उस प्राधिकारी की स्वयं अपने निकषपों को ध्यान में रखते हुए या ऐसे किसी जांच प्राधिकारी के, जिसे उसने नियुक्त किया हो, निकषपों में से किसी पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के और खण्ड (iv) से (viii) में विनिरिप्ट शास्त्रियों सेवक पर अधिगोपित की जानी चाहिए, वहां वह प्राधिकारी जांच का अधिले द्वारा ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा जो वर्णित शास्त्रियों अधिगोपित करने के लिए सक्षम है।
- (ख) वह अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको अभिलेख इस प्रकार भेजे जाते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य पर कार्यालयी कर सकेगा या यदि उसकी राय है कि मालियों में से किसी साक्षी की अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह उस साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उस साक्षी की परीक्षा प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा और सेवक पर ऐसा शास्त्र अधिगोपित कर सकेगा जो वह इन नियमों के अनुसार ठीक नहीं।
- (22) जब कभी कोई जांच प्राधिकारी किसी जांच में साक्ष्य को पूर्णतः या भौगोलिक अधिलिखित किए जाने के पश्चात् उसमें अधिकारिता का प्रयोग करना बन्द कर देता
- है और कोई ग्रन्थ जांच प्राधिकारी जिसे ऐसी अधिकारिता है और जो उसका प्रयोग करता है उसका उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा ऐसी अभिलिखित या अपने पूर्ववर्ती द्वारा भागतः प्रभिलिखित और भागतः अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकते हैं।
- परन्तु यदि उत्तरवर्ती जांच प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे साक्षियों में से किसी की, जिसका मालिय पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्यायालय के हित में आवश्यक है, वह तो वह ऐसे किसी भी साक्षियोः को पुनः बुला सकेगा, उनकी परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, इसमें इसके पूर्व उपबन्धित रीति से कर सकेगा।
- 23(1) जांच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसमें निम्नलिखित बातें होंगी:—
- (क) आरोप के अनुच्छेद तथा अवचार और कदाचार के साथमां का विवरण ;
- (ख) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत कर्मचारी की प्रतिरक्षा :
- (ग) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण ;
- (घ) आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उसके लिए कारण।
- स्पष्टीकरण:—यदि जांच प्राधिकारी की राय में, जांच की कार्यवाही में आरोप का ऐसा कोई अनुच्छेद साक्षित होता है जो आरोप के मूल अनुच्छेदों से भिन्न है, तो वह आरोप के ऐसे अनुच्छेद पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा; परन्तु आरोप के प्रत्येक ऐसे अनुच्छेद पर निष्कर्ष तब तक नहीं अभिलिखित किए जाएंगे जब तक कि सेवक उन तथ्यों को, जिन पर आरोप का ऐसा अनुच्छेद आधारित है, स्वीकार नहीं कर लेता है या उसको आरोप के ऐसे अनुच्छेद के विश्व प्रपत्ति प्रतिरक्षा करने का युक्ति युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।
- (2) जांच प्राधिकारी, जहां कि वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है, अनुशासनिक प्राधिकारी को, जांच का ऐसा अभिलेख भेजेगा जिसमें निम्नलिखित होंगी:—
- (क) वह रिपोर्ट जो उसने खण्ड (i) के मध्यम तैयार की है;
- (ख) सेवक द्वारा पेश की गई प्रतिरक्षा का, यदि कोई है, लिखित कथन ;
- (ग) जांच के दौरान पेश किया गया मौखिक और इस्तावेजी साक्ष्य ;
- (घ) जांच के दौरान उपस्थित प्राधिकारी या सेवक या दोनों द्वारा काल लिखित संक्षेप, यदि कोई है और
- (ड) अनुशासनिक प्राधिकारी और जांच प्राधिकारी द्वारा जांच की बाबत किए गए आदेश, यदि कोई है।
- “12.-क(1) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह स्वयं जांच प्राधिकारी नहीं है, उन कारणों से जो सेवक द्वारा किए जाएंगे, मामले को प्रतिरक्षा जांच और रिपोर्ट के लिए जांच प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेगा और जांच प्राधिकारी, तबुपरियावतस्थ नियम 12 के उपबन्धों के अनुसार अनिरिक्त जांच करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।

- (2) अनुशासनिक प्राधिकारी, यदि वह आरोप के किसी अनुच्छेद पर जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है, ऐसी अनुशासनिक के लिए अपने कारणों को अधिलिखित करेगा और यदि वह साक्ष्य, जो अभिलेख पर है, उम प्रयोजन के लिए पर्याप्त है, तो वह ऐसे आरोप पर स्वयं अपने निष्कर्ष अधिलिखित करेगा।
- (3) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप के सभी या किन्ही अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को व्याप में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो नियम 12 में किसी बात के होते हुए भी, वह ऐसी शास्त्र अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा।
- (4) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप से सभी या किन्ही अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्षों को व्याप में रखते हुए यह राय है कि नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) से (viii) में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्त्र अधिरोपित करने वाला आदेश करेगा और जांच के बौरान वेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित या अधिरोपित शास्त्र के विनष्ट अध्यावेदन करने का आवश्यक नहीं होगा:
12. (ख) (1) नियम 12 के उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम 11 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिरोपित करने वाला आदेश किए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित या अधिरोपित शास्त्र के विनष्ट अध्यावेदन करने का आवश्यक नहीं होगा:-
- (क) सेवक को उसके विषय कार्यवाही करने की प्रस्थापना की ओर अबचार या कदाचार के लाभों की जिन पर कार्यवाही के किए जाने की प्रस्थापना है लिखित सूचना देने और उसे ऐसा अध्यावेदन करने का जैसा वह प्रस्थापना के विनष्ट करना चाहे युक्तिमुक्त भवसर दें दिए जाने;
- (ख) नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकारित रीत से ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी जांच आवश्यक है, जांच करने;
- (ग) खण्ड (क) के अधीन सेवक द्वारा दिए गए अध्यावेदन यदि कोई गई है, और खण्ड (ख) के अधीन की गई जांच, यदि कोई की गई है, अभिलेख पर विचार करने, और
- (घ) अबचार या कदाचार के प्रत्येक लाभन पर निष्कर्ष अधिलिखित करने;
- के पश्चात ही किया जाएगा अस्या नहीं।
- (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी मामले में, सेवक द्वारा इस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन दिए गए अध्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात यह प्रत्यापित किया जाता है कि वेतन वृद्धियाँ, रोक दी जाएँ और ऐसी वेतन वृद्धियाँ रोकने की शास्त्र से सेवक को देय मेंशन की रकम पर प्रतिकूल प्रभाव पृथके की संभावना है या तीन वर्ष से प्राधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धियाँ रोक दी जाएँ या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियाँ रोक दी जाएँ तो सेवक पर ऐसी कोई शास्त्र अधिरोपित करने वाला आदेश करने से पूर्व नियम 12 के उपनियम (3) से (23) में अधिकारित रीत से जांच की जाएगी।
- (3) ऐसे मामलों में कार्यवाहीयों के अभिलेख में निम्नलिखित होंगे—
- सेवक के विषय कार्यवाही करने की प्रस्थापना की व्याप में गई संमूचना की एक प्रति;
 - उसको परिदृष्ट अबचार या कदाचार के लाभों के विचार की एक प्रति;
 - उसका अध्यावेदन, यदि कोई है;
 - जांच के बौरान वेश किया गया साक्ष्य;
 - अबचार या कदाचार के प्रत्येक लाभन पर निष्कर्ष ; और
 - मामले में आदेश तथा उसके लिए कारण।
- 12ग. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश, सेवक को संस्थित किए जाएंगे और उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जांच, यदि कोई है, की रिपोर्ट की एक प्रति और आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद पर उसके निष्कर्षों की एक प्रति भी दी जाएगी या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जांच प्राधिकारी महीं है, वहाँ जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्षों का एक विवरण दिया जाएगा तथा जांच प्राधिकारी के निष्कर्षों से उसकी असहमति, यदि कोई है, के लिए संक्षिप्त कारण भी दिय जाएगे, यदि वे पहले ही से उसे नहीं दिए गए हैं।
- 12ग. (1) जहाँ किसी मामले में दो या भविष्यक सेवक संबद्ध हैं वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी जो ऐसे सभी सेवकों पर सेवा से विचारित की शास्त्र अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, यह निदेश देते हुए आदेश कर सकता कि उन सभी के विषय एक ही कार्यवाही में अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- 12ग. (2) नियम 12 में 12व भी किसी बात के होते हुए भी, —
- जहाँ किसी सेवक पर कोई शास्त्र ऐसे आबरण के आधार पर अधिरोपित की जाती है कि जिसके कारण उसकी किसी आपाराधिक आरोप पर दोषसिद्ध हुई है;
 - जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का उस कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीत से जांच करना युक्तिमुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसे आदेश करेगा जो वह की समझता है।
- 12व. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विषय अपील नहीं होगी—
- अन्तवर्ती प्रकृति का कोई आदेश या निलम्बन आदेश से भिन्न ऐसा आदेश जो अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम निपटारे के लिए सहायक है;
 - नियम 12 के अधीन जांच के अनुक्रम में जांच प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश।
15. उक्त नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में, “और यथा किसी अच्छी या खराब सेवा के प्रति निर्वेश” शब्दों का लोप किया जाएगा।
16. उक्त नियमों के नियम 39 में उपनियम (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, प्रधानतः—
- “परस्तु किसी ऐसे सेवक को, जिसे छावनी की वस्तुओं आदि का दुर्विधियोग, गवन, या चोरी के लिए दोषी पाया गया है या जिसे छावनी की वस्तुओं के दुर्विधियोग, गवन या चोरी का पता लगाने की हारीख के पश्चात् पदच्युत किया या पत से हटाया

गया है या उस तारीख के पश्चात् जिस तारीख को इन नियमों के अधीन ऐसे सेवक के विशद् अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ की गई जिसके परिणामस्थल उसे सेवा से पदच्छ्रव किया या हटाया गया, वालम का 'सदाय नहीं किया जाएगा।'

[न० 25/133/सी/एल एड मी/69/3406-सी/ओ/(क्षु. एड मी)]

New Delhi, the 31st December, 1980

S.R.O. 5.—The following draft of certain rules further to amend the Cantonment Funds Servants Rules, 1937 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Section 280 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) is hereby published, as required by sub-section (1) of the said section 280, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period of sixty days so specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Cantonment Fund Servants (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Cantonment Funds Servants Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,

(i) after clause (a) the following clause shall be inserted, namely :—

"(aa) "appointing authority" in relation to a Cantonment Fund Servant means (i) the authority empowered to make appointments to the post which the servant for the time being holds, or (ii) the authority which appointed the servant to such post as the case may be, whichever authority is the higher authority";

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

"(cc) "disciplinary authority" means the authority competent under these rules to impose on a servant any of the penalties specified in rule 11";

(iii) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely :—

"(dd) "non-supervisory post" means any appointment under a Board which is not a "supervisory post";"

(iv) in clause (f), the words "but does not include any servant who may be serving in the post which is pensionable from public revenues" shall be omitted;

(v) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(f) "supervisory post" means any appointment under a Board which has been declared as a Supervisory post by the Central Government or such authority as may be authorised by it in this behalf";

(vi) for clause (h) the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) "temporary servant" in relation to a Cantonment Fund Servant includes besides the incumbent of a temporary post sanctioned under rule 9, the incumbent on a temporary basis of a substantive or permanent post under the Board".

3. In rule 3 of the said rules, the words "and subsequently modified under the Government of India Act, 1935", shall be omitted.

4. In the first proviso to rule 5 of the said rules, for the words "not less than fifty rupees per mensem", the words "not less than two hundred and fifty rupees per mensem" shall be substituted.

5. In rule 5-B of the said rules,—

(a) in sub-rule (3) after the existing proviso, the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—Authorised medical attendant for the purpose of this rule means the Medical Officer appointed by the Board to attend on the servant of the Board".

(b) In sub-rule (8) for the words "by each Board", the words "by the appointing authority" shall be substituted.

6. For sub-rule (1) of rule 7 of the said rules, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) All appointments to supervisory posts shall be made by the Board and to non-supervisory posts by the Executive Officer".

7. In clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 of the rules, after the words "qualified service", the following words shall be inserted, namely :—

"subject to such directions as the Central Government may issue from time to time in this regard".

8. In rule 8 of the said rules,—

(i) in sub rule (4), for the opening words "The Board", the words "The Executive Officer", shall be substituted;

(ii) after the proviso to sub-rule (5), the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided further that the service of a temporary servant shall be liable to termination at any time by a notice given by the appointing authority to the servant. The period of such notice shall be one month but notwithstanding the same the service of any such servant may be terminated forthwith. On such termination the servant shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing immediately before the termination of service or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month".

9. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely :—

"9. when in the opinion of the President of the Board, the employment of temporary servants is necessary, he may sanction creation of such temporary posts for an aggregate period not exceeding six months on such conditions as may be considered necessary and appointment to such posts shall be made by the appointing authority concerned :

Provided that,—

(a) the President of the Board in the exercise of this power shall not act in contravention of an order of the Board prohibiting the creation of temporary posts for any particular work, and shall report in writing every appointment made under the rule by the Executive Officer for the approval of the Board at the next meeting :

(b) all such appointments shall be reported by the President of the Board to the Officer Commanding-in-Chief, the Command, for confirmation, the report being made after the approval of the Board has been obtained in accordance with clause (a), and being accompanied by a full explanation of the conditions which have given rise to the appointments ; and

(c) if the approval of the Board or the confirmation of the Officer Commanding-in-Chief, the Command, is withheld in the case of any such appointment, the appointment shall be terminated forthwith."

10 After rule 10 of the said rules the following rule shall be inserted namely —

10A (1) the appointing authority may place a servant under suspension,—

(i) Where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or

(b) Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation inquiry or trial

(2) A servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority —

(a) With effect from the date of his detention if he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours

(b) With effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction

Explanation—The period of the forty-eight hours referred to in clause (b) of this subrule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent period of imprisonment, if any shall be taken into account

(3) Where a penalty of dismissal removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further enquiry or action or with any directions the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders

(4) Where a penalty of dismissal removal or compulsory retirement from service imposed upon a servant is set aside or declared of rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstance of the case, decides to hold a further enquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed the servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders

(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so

(b) Where a servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension the authority competent to place him under suspension may for reasons to be recorded by him in writing direct that the servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any such proceedings

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate”

11 For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted namely —

11 (1) The following penalties may, for good and sufficient reasons to be recorded in writing be imposed by the Executive Officer on a servant namely —

Minor Penalties—

(i) Censure

(ii) Fine

(2) The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed by the appointing authority on a servant namely —

Minor Penalties—

(i) Withholding of his promotion

(ii) Recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Board by negligence or breach of order,

(iii) Withholding of increment of pay

Major Penalties—

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the servant will earn increments or pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay,

(v) reduction to lower time-scale or pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the servant to the time-scale or pay grade post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service

(vi) compulsory retirement

(vii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Board in whose service he was at the time of such removal or any other Board,

(viii) dismissal from service which shall ordinarily be disqualification for future employment under the Board under whom he was employed at the time of dismissal or any other Board

Explanation—The following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely —

(i) stoppage of a servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar

(ii) non-promotion of a servant whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case to a service grade or post for promotion to which he is eligible

(iii) reversion of a servant officiating in higher service, grade or post to a lower service grade or post, on the ground that he is considered to be unsuitable for such higher service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct,

(iv) reversion of a servant appointed on probation to any other service grade or post to his permanent service grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation,

(v) compulsory retirement of a servant in accordance with the provisions relating to his superannuation or retirement and

(vi) termination of the services—

(a) of a servant appointed on probation during or at the end of the period of his probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or

- (b) of a temporary servant in accordance with the provisions of sub-rule (5) of rule 8; or
- (c) of a servant, employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement:

Provided that—

- (i) no fine shall be imposed on any servant other than a lower grade servant and in no case shall the aggregate of fine in any month exceed such limit as may, from time to time, be specified by the Central Government;
- (ii) a list of punishments, inflicted under this rule by the Executive Officer, shall be submitted monthly to the Board."

12. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"11A. Disciplinary proceedings against a servant may be initiated by the appointing authority."

13. For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"12. (1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of rule 11 shall be made except after an enquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and rule 12A.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule, as the case may be, any authority to enquire into the truth thereof.

Explanation.—Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in rules to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a servant under this rule and rule 12-A, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up,—

- (i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge;
- (ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge which shall contain :
 - (a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the servant;
 - (b) a list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the servant a copy of the articles of charge, the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charges is proposed to be sustained and shall require the servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may itself inquire into such of the articles of charge as are not admitted or, if it considers it necessary to do so, appoint under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose, and where all the articles of charge have been admitted by the servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record its findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act in the manner laid down in rule 12A.

(b) If no written statement of defence is submitted by the servant the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge, or may if it considers it necessary to do so, appoint, under sub-rule (2) an inquiring authority for the purpose;

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding any inquiry into such charge, it may, by an order, appoint a servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on its behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward to the inquiring authority,—

- (i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the servant;
- (iii) a copy of the statements of witnesses, if any, referred to in sub rule (3);
- (iv) evidence proving the delivery of the documents referred to in sub rule (3) to the servant; and
- (v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer."

(7) The servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge, and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour, as the inquiring authority may, by notice in writing, specify, in this behalf, or within such further time, not exceeding ten days, as the inquiring authority may allow.

(8) (a) The servant may take the assistance of any other servant to present the case on his behalf but may not engage a legal practitioner for the purpose unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits.

Note.—The servant shall not take the assistance of any other servant who has two pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The servant may also take the assistance of a retired servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Central Government from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the servant who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority, such authority shall ask him whether he is guilty or has any defence to make and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the servant pleads guilty...

(11) The inquiring authority shall, if the servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the presenting officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the servant may, for the purpose of preparing his defence:—

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list referred to sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time not exceeding ten days as the inquiring authority may allow: for the discovery or production of any documents which are in the possession of the board but not mentioned in the list referred to in sub-rule (3).

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the documents by such date as may be specified in such requisition:

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition referred to in sub-rule (12), every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority:

Provided that if the authority having the custody or possession of the requisitioned documents is satisfied for reason to be recorded in writing that the production of all or any of such documents would be against the public interest, it shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of documents.

(14) On the date fixed for inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter, without the leave of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the servant shall be entitled to have, if he demands it a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the servant to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary, in the interests of justice.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded, and the servant shall be required to sign the record. In either case, a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the servant shall then be produced. The servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the servant shall then be examined and shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the servant closes his case, and shall, if the servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer, if any appointed, and the servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the

purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry ex parte.

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clause (1) and sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 (but not competent to impose any of penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11), has itself inquired into or caused to be inquired into the articles of any charge and that authority, having regard to its own findings or having regard to its decision on any of the findings or any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in sub-clauses (iv) to (viii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, that authority shall forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the last mentioned penalties.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the record or may, if it is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interest of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the servant such penalty as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction herein, and is succeeded by another inquiring authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself;

Provided that if the succeeding inquiry authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, it may, recall, examine, cross-examine and re-examine, any such witness as hereinbefore provided.

(23) (1) After the conclusion of the inquiry, a report shall be prepared and it shall contain—

- (a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;
- (b) the defence of the servant in respect of each article of charge;
- (c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge;
- (d) the findings on each article of charge and reasons therefor.

EXPLANATION

If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry establish any article of charge different from the original articles of the charge, it may record its findings on such article of charge :

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

- (2) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include—
 - (a) the report prepared by it under clause (i);
 - (b) the written statement of defence, if any, submitted by the servant;
 - (c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry;
 - (d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the servant or both during the course of the inquiry; and
 - (e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

14. For rule 12A of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"12A. (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded in writing remit the case to the inquiring authority for further inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 12, as far as may be.

(2) The disciplinary authority shall, if it is disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge if the evidence on record is sufficient for the purpose.

(3) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that any of the penalties specified in sub-clauses (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be imposed on the servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule 12, make an order imposing such penalty.

(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (iv) to (viii) of clause (2) rule 11 should be imposed on the servant, it shall make an order imposing such penalty and it should not be necessary to give the servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed.

12B (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 12A, no order imposing on a servant any of the penalties specified in sub-clause (i) to (iii) of clause (2) of rule 11 shall be made except after :—

- (a) informing the servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;
- (b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 12, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;
- (c) taking the representation, if any, submitted by the servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration; and
- (d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour.

"(2) Notwithstanding anything contained in clause (b) of sub-rule (1), if in a case it is proposed after considering the representation, if any, made by the servant under clause (a) of that sub-rule to withhold increments of pay and such withholding of increments is likely to affect adversely the amount of pension payable to the servant or to withhold increments of pay for a period exceeding three years or to withhold increments, if any, with cumulative effect for any period, an inquiry shall be held in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 12, before making any order imposing on the servant any such penalty.

(3) The record of proceedings in such cases shall include—

- (i) a copy of the intimation to the servant of the proposal to take action against him;
- (ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him;
- (iii) his representation ; if any ;
- (iv) the evidence produced during the inquiry;
- (v) the findings on each imputation of misconduct or misbehaviour; and
- (vi) the orders on the case together with the reasons therefor.

12C.—Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the servant who shall also be supplied with a copy of the report of the inquiry, if any, held by the disciplinary authority and copy of its findings on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiry authority, a copy of the report of the inquiring authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority unless they have already been supplied to him.

12D.—Where two or more servants are concerned in any case, the disciplinary authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

12E.—Notwithstanding anything contained in rules 12 to 12D :

- (i) Where any penalty is imposed on a servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or
- (ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by it in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these rules, the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit.

12F. Notwithstanding anything contained in these rules no appeal shall lie against—

- (i) any order of an interlocutory nature or of the nature of a stay-in-aid for the final disposal of a disciplinary proceeding, other than an order of suspension;
- (ii) any order passed by an inquiring authority in the course of an inquiry under rule 12."

15. In sub-rule (1) of rule 19 of the said rules, the words "and references to any good or bad services shall, as occasion arises" shall be omitted.

16. In rule 39 of the said rules, after clause (c) of sub-rule (2) the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that no such bonus shall be paid to any servant who has been found guilty of misappropriation, embezzlement or theft of cantonment stores, etc. or has been dismissed or removed from service of the

Board for any period subsequent to the date of detection of such misappropriation, embezzlement or theft of Cantonment Stores or date on which disciplinary proceedings under these rules have been initiated against such servant resulting in his removal or dismissal from service."

[F. No. 25/133/C/L&C/69/3406-C/D (Q&C)]

नई दिल्ली, ३ जनवरी, १९८१

का० नि० आ० ६.—छावनी प्रधानियम, १९२४ (१९२४ का २) की घारा १३ की उपधारा (७) ना अतगरण करने हुए केन्द्रीय सरकार एवं द्वारा प्रधिसूचित करती है कि छावनी ओर्डर फिरोजपुर के निम्नलिखित व्यक्ति, उनके नामने दर्शित शब्दों से, महस्य निर्वाचित हुए हैं—

१ श्री थसन मिह	वार्ड स० I
२ श्री बलदेव राज	वार्ड स० II
३ श्री मवन लाल	वार्ड स० III
४ श्री विजय कुमार	वार्ड स० IV
५ श्री चरनजीत सिंह महान	वार्ड स० V

६ श्री हम गज

वार्ड स० VI

७ श्री आर्द० श्री० फार्मिस

वार्ड स० VII

[फाइल स० 29/33/सी/एलएण्ड सी/77/9/सी/शी (कूपूण्ड सी)]

प्रादिश्य कृष्ण, प्रबंग मन्त्री

New Delhi, the 2nd January, 1981

S.R.O. 6.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Ferozepur from the wards noted against each :—

1. Shri Wasan Singh	Ward No. I
2. „ Baldev Raj	„ „ II
3. „ Madan Lal	„ „ III
4. „ Vijay Kumar	„ „ IV
5. „ Charanjit Singh Sehgal	„ „ V
6. „ Hans Raj	„ „ VI
7. „ L.B. Francis	„ „ VII

[File No. 29/33/C/L & C/77/9-C/D/(Q & C)]

ADITYA KUMAR, Under Secy.

